

विचार बिन्दु

अकर्मण्यता के जीवन से यशस्वी जीवन और यशस्वी मृत्यु श्रेष्ठ होती है।

—चंद्रशेखर वेंकट रमण

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति केवल कागज़ों में

ल गभग तीन साल पहले बड़े जोर-शोर से भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति घोषित की थी। इस नीति का प्रारूप प्रसिद्ध वैज्ञानिक कस्तुरी रंगन की अध्यक्षता में गठित समिति ने तैयार किया था। इससे पूर्व सेवानिवृत्त कैबिनेट सचिव टी सुब्रह्मण्यम की अध्यक्षता वाली समिति ने देश की सभी प्राम पंचायत और शिक्षा विदों से प्राप्त सुझावों पर विचार किया था। इस नीति के बनते-बनते तीन शिक्षा मंत्री बदल गए। सबसे पहले स्मृति इंदानी ने प्रक्रिया प्रारंभ की और देश की सभी 2.50 लाख पंचायतों से सुझाव आमंत्रित किए। इसके बाद प्रकाश जावडेकर शिक्षा मंत्री बने और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, किन्तु वे इसे अंतिम रूप नहीं दे पाए। 2020 में इसे रमेश पोखरियाल, ने इसे अंततः जुलाई 2020 में जारी किया।

इस नई नीति को घोषित हुए तीन साल हो चुके हैं किन्तु धरातल पर अब तक इसका कोई क्रियाव्यवस्था देखने में नहीं आया है। नीति को घोषित करते समय इसे शिक्षा में क्रांति लाने वाली नीति के रूप में प्रचारित-प्रसारित किया गया।

पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में बनी और दूसरी 1986 में बनी, जिसे 1992 में संशोधित किया गया। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोटारी आयोग द्वारा बनाई गई। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर डी एस कोटारी राजस्थान के ही रहने वाले प्रसिद्ध शिक्षा विद और वैज्ञानिक थे। यह प्रभुभूमि इसलिए दी गई है ताकि पाठक समझ सकें कि इस नीति को बनाने में कितने लोगों का कितना प्रयास लगा और धन भी लगा। इसके बावजूद यदि यह नीति लागू ही नहीं हो पा रही है तो इसके कारणों का विवेचन और विश्लेषण करना उपयुक्त होगा।

सबसे पहला कारण तो वही जो लगभग सभी सरकारी नीतियों के साथ होता है। नीति बनाने वाले धरातल की वास्तविकताओं का कोई ध्यान, नीति बनाने समय नहीं रखते। आदर्श नीतियाँ तब ही क्रियान्वित हो सकती हैं जब परिस्थितियाँ आदर्श हों। हमारे यहाँ तो स्थिति ठीक इसके विपरीत है। यह नीति के कुछ प्रावधानों से स्पष्ट हो जाएगा।

1986 की शिक्षा नीति में शिक्षा का ढांचा 10 + 2 + 3 का था। स्कूली शिक्षा को विभाजित करने के बाद यह व्यवस्था 5 + 3 + 2 + 2 हो गई, अर्थात् प्रारंभिक पांच वर्ष को प्राथमिक स्तर का नाम दिया गया। बाद के 3 साल को उच्च प्राथमिक, आगामी 2 वर्ष माध्यमिक तथा अंतिम 2 वर्ष को उच्च माध्यमिक शिक्षा का नाम दिया गया। कुछ राज्यों में दसवीं के बाद 2 वर्ष को पढाई जूनियर कॉलेज में रूप में होती थी एवं अधिकांश राज्यों में यह विद्यालयों में ही उच्च माध्यमिक शिक्षा के नाम से हुई। यह व्यवस्था कई सालों तक नियमित रूप से चलती रही। अब जबकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है तो इस ढांचे को बदलकर 5 + 3 + 3 + 4 किया गया है। इसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा को नर्सरी से लेकर कक्षा दो तक का बना गया एवं उसके बाद 3 वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा, उसके बाद 3 साल तक उच्च माध्यमिक शिक्षा एवं अंतिम 4 वर्ष माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का नाम दिया गया है। वर्तमान में सभी विद्यालयों, विशेषकर राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक संचालित होती है। पूर्व प्राथमिक की नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी अधिकतर प्ले स्कूल के नाम से चलाये जाते हैं। वर्तमान में जब सभी विद्यालयों में विशेषकर सरकारी विद्यालयों में कक्षा एक से पढाई प्रारंभ होती है तो पहली से पूर्व की तीन कक्षाओं के बच्चों को स्कूल को पढाने की व्यवस्था क्या होगी इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं को पढाने के लिए विशेष तरह की योग्यता की आवश्यकता होती है जो सामान्यतया एन टी टी (नर्सरी टीचर ट्रेनिंग) में विकसित की जाती है। वर्तमान व्यवस्था में एनटीटी किए हुए लोगों को तो शिक्षा विभाग में भर्ती के योग्य ही नहीं माना गया है। इन कक्षाओं को पढाई कौन कराएगा और कैसे होगी इस बारे में कोई स्पष्टता न नीति में है न राज्य स्तर पर।

वर्तमान में अधिकांश स्थानों पर आंगनवाड़ी में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान है, किन्तु यह काम गौण ही है क्योंकि आंगनवाड़ियों के पास अन्य कई महत्वपूर्ण कार्य सौंपे हुए हैं। वास्तविकता यह है कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को उपयुक्त पूर्व प्राथमिक शिक्षा देने की क्षमता न तो वर्तमान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में है न ही वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों में है, जो सामान्यतः बीएसटीसी या बी एड होते हैं। यदि स्कूलों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं चलाई जानी हैं तो बड़ी संख्या में अपेक्षित योग्यता धारी शिक्षकों की भर्ती करनी होगी। वर्तमान में तो स्थिति यह है कि देश में लाखों पर शिक्षकों के पहले ही रिक्त हैं। कई विद्यालय केवल बिना शिक्षक या एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। इसी कारण यह आशंका स्वाभाविक है कि नई व्यवस्था केवल फाइलों में बंद होकर न रह जाए।

सरकार के नीति निर्धारकों को यह समझना होगा कि सुदृढ़ एवं गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा किसी भी बच्चे के भविष्य के लिए नींव का काम करती है। यदि यह यूं ही कमजोर रही तो उस पर बनाई गई इमारत टिक नहीं पाएगी। इसकी संभावना नई शिक्षा नीति के माध्यम से भी नहीं लगती है।

दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह है कि स्थानीय बोली को माध्यम बनकर ही पूर्व प्राथमिक कक्षा के बच्चों को शिक्षा दी जाए ताकि बच्चे सहजता के साथ उसे ग्रहण कर सकें। उसके बाद प्राथमिक स्तर पर तो निश्चित रूप से उसे स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए और यथासंभव अगली कक्षाओं में भी स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाए। वर्तमान में तथाकथित श्रेष्ठ विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देते हैं और अधिभावक भी बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढाने को वरीयता देते हैं।

राजस्थान सरकार ने तो एक कदम आगे बढ़कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना के ठीक विपरीत 2000 विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम का बना दिया है। एक सर्वमान्य तथ्य है कि अंग्रेजी को एक भाषा की तरह पढना और उस पर अधिकार प्राप्त करना आज के युग में उपयोगी हो सकता है किन्तु इसके लिए अंग्रेजी माध्यम से पढाई करना बेतुका निर्णय ही कहा जाएगा। जिन शिक्षकों ने वर्षों से हिंदी माध्यम से पढाया है उनसे अचानक अंग्रेजी माध्यम में सभी विषय पढाने के लिए कहना केवल आदेश मात्र बनकर रह जाएगा। यह देखा गया है कि अंग्रेजी माध्यम के सरकारी विद्यालयों में प्रवेश लेने की होड़ मची थी, वहीं अब अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में न तो शिक्षक जाना चाहते हैं एवं न ही बच्चे। शायद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलना राजस्थान के सरकारी विद्यालयों के परिप्रेक्ष्य में अदूरदर्शिता पूर्ण निर्णय ही कहा जाएगा। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की भावना के विपरीत तो है ही, साथ ही बच्चों के हित के भी विपरीत है। जो बच्चे अपने घरों में स्थानीय बोली में बात करते हैं और हिंदी भी सही रूप से नहीं बोल पाते हैं, उन्हें अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देना इसी बात को संकेत करता है कि शिक्षा के नीति निर्धारकों का धरातल की वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है। यही कारण है कि शिक्षा की गुणवत्ता दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है। राजकीय विद्यालयों की बात छोड़ें, जो हैं, तो क्या अधिजात्य वर्ग के विद्यालयों को इस बात के लिए बाध्य किया जा सकेगा कि वह अंग्रेजी माध्यम को छोड़कर अब स्थानीय भाषा में बच्चों को शिक्षा दें? इन विद्यालयों के संचालकों का सरकार पर प्रभाव देखते हुए तो ऐसा होना फिलहाल संभव दिखाई नहीं देता है।

एक बहुत आदर्श बात नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कही गई है कि कला, वाणिज्य और विज्ञान आदि संकाय के मध्य किसी प्रकार का विभाजन नहीं होगा और कोई भी विद्यार्थी अलग-अलग विषय की शिक्षा प्राप्त कर सकेगा। अर्थात्, दो विषय विज्ञान के लेकर और एक विषय कला का ले सकेगा अथवा दो विषय कला के लेकर एक विषय वाणिज्य का ले सकेगा। इस प्रकार का लचीलापन विदेशों की सामान्य शिक्षा व्यवस्था में है किन्तु इसके लिए वर्तमान में उपलब्ध शिक्षकों की संख्या को कई गुना बढ़ाना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो यह केवल एक हवाई घोषणा बनकर ही रह जाएगी। वर्तमान में, अधिकांश विद्यालयों में विज्ञान के शिक्षक ही उपलब्ध नहीं हैं जबकि सरकार ने मनमानी तरह से 12वीं तक के विद्यालय खोल दिए हैं।

जो बात शिक्षा नीति में होनी चाहिए थी और जो नहीं है वह यह कि प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा स्थानीय सन्दर्भ को ध्यान में रखकर दी जानी चाहिए। ऐसी शिक्षा का क्या लाभ है, जिसमें बच्चा अपने आप को जोड़ नहीं सके। भाषा और गणित को स्थानीय रूप से उपलब्ध सामान्य परिस्थितियों के आधार पर पढाया जा सकता है। संस्कृति, भूगोल, इतिहास, रहन-सहन, खाने-पीने आदि में जितनी विविधता भारत में है, शायद ही विश्व के किसी देश में हो। बच्चों की शिक्षा को सहज और सुगम बनाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि बच्चा शिक्षा से अपने आपको जुड़ा महसूस कर सके। यह उभरी हो पाएगा जब स्थानीय सन्दर्भ को आधार बनाकर शिक्षा प्रदान की जाए। पांचवी कक्षा तक तो किसी पाठ्यपुस्तक की कोई आवश्यकता नहीं है। शिक्षक स्वयं अपने स्तर पर नवाचारी शिक्षण विधियों को अपनाकर शिक्षण सामग्री तैयार कर सकता है, और उसके आधार पर बच्चों को इस प्रकार से शिक्षा प्रदान कर सकता है जो उसे अपनी भी लगे और रुचिकर भी। ऐसा होने पर अधिभावकों को भी लगेगा कि बच्चों को काम की शिक्षा मिल रही है। कई बार अधिभावकों द्वारा बच्चों को विद्यालयों से निकालने का कारण यह होता है कि उन्हें शिक्षा, जीवन के लिए उपयोगी नहीं लगती। शिक्षा को जीवन उपयोगी बनाने के लिए जो बातें नई शिक्षा नीति में लिखी भी गई हैं, उन्हें लागू करने की क्षमता शिक्षकों में होना अनिवार्य है। तब ही वे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं।

सरकार के नीति निर्धारकों को यह समझना होगा कि सुदृढ़ एवं गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा किसी भी बच्चे के भविष्य के लिए नींव का काम करती है। यदि यह यूं ही कमजोर रही तो उस पर बनाई गई इमारत टिक नहीं पाएगी। इसकी संभावना नई शिक्षा नीति के माध्यम से भी नहीं लगती है। आजकल, बच्चों को केवल जानकारी देने से कोई लाभ नहीं है क्योंकि जानकारी तो वह घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से गूगल करके आसानी से प्राप्त कर सकता है। उसे आवश्यकता इस प्रकार की शिक्षा देने की है जो उसके दिन-प्रतिदिन जीवन में काम आ सके। जो बच्चे स्कूल के बाद आगे की पढाई जारी नहीं रख पाएँ, है वे भी इतना सक्षम तो हो ही जायें कि वे विश्वास पूर्वक अपना जीविकोपार्जन कर सकें।

अंत में यही कहा जा सकता है कि शिक्षा की मूल समस्याओं को समझे बिना कोई भी नीति सफल नहीं हो सकती। जैसे शिक्षकों के स्थानान्तरण को व्यवस्था को समाप्त करना, शिक्षकों के चयन को अधिक युक्तिसंगत बनाना, पाठ्य सामग्री को संदर्भ आधारित बनाना, शिक्षकों के पदों को तत्काल सभ्य बना आदि शिक्षकों को इस प्रकार से प्रशिक्षित करना होगा कि वह बच्चों की नींव को मजबूत कर सकें। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने भी इस कमी को महसूस करते हुए सामान्य लिखने-पढने और जोड़-बाकी की योग्यता, पांचवी कक्षा के शत प्रतिशत बच्चों में विकसित करने का मिशन प्रारंभ किया है। हालांकि शिक्षा समन्वयी सूची का विषय है, राज्य सरकार इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दे, तो कोई कारण नहीं कि हम बच्चों के भविष्य के लिए मजबूत नींव प्रदान न कर सकें। जहाँ तक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रश्न है, उसके तो कागज़ों से बाहर निकल पाने की संभावना कम ही है। राज्य यदि इसके विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठा रहे है तो वह इसलिए कि किसी ने इसे गंभीरता पूर्वक लागू करने का प्रयास नहीं किया।

क्या राजस्थान के बच्चे आशा कर सकते हैं कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक और अन्य शिक्षा अधिकारी बच्चों को उनके लिए उपयोगी शिक्षा देने का प्रयास करेंगे, बजाए इसके कि उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाय जिसका उनके जीवन में कतई उपयोग नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान में लोक जुम्हिय, शिक्षा कर्मी जैसे सफल प्रयोगों से सीखा जाय।

—अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भागवत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

जर्जर टंकी से भयभीत वॉर्डवासी, लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है

सुजानगढ़, (निसं)। वार्ड 49 में जलदाय विभाग की जर्जर टंकी हदसों को निमंत्रण दे रही है। सोमवार को जर्जर टंकी से लाखों लीटर पानी व्यर्थ बहा, जिसके बाद भयभीत वार्डवासीयों ने जलदाय विभाग को सूचना दी। सूचना पर जलदाय विभाग के कपिल प्रजापत ने मौके पर पहुंचकर टंकी के नीचे का बॉल को बंद कर व्यर्थ बह रहे पानी को रोका।

पार्श्व प्रतिनिधि कमल दाधीच ने बताया कि विधायक मनोज मेघवाल को उन्होंने वार्डवासीयों के साथ टूटी टंकी को गिराने के लिए ज्ञापन दिया था। लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। लापरवाह अधिकारी जर्जर टंकी से आमजन के बचाव के लिए किसी प्रकार का साइन

- जलदाय विभाग के अधिकारियों को बड़े हादसे का इंतजार
- लोगों ने बताया कि टंकी का निर्माण 30 साल पहले हुआ था

बोर्ड भी नहीं लगा रहे है। पेयजल टंकी के सामने रहने वाले श्रीचंद पारीक ने बताया कि टंकी का निर्माण 30 साल पहले हुआ था जो अब पूर्णतया जर्जर हो चुकी है। पारीक ने बताया जर्जर टंकी को देखकर उनके मन में टंकी के गिरने का भय बना रहता है। अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि भी उनकी समस्या को

गंभीरता से नहीं ले रहे है।

वार्ड के विकास पारीक ने कहा कि रोज टंकी का जर्जर हिस्सा सड़क पर गिरता है। सड़क से गुजरने वाले राहगीर भी यहां से गुजरते समय भय के माहौल में गुजरते है। कई बार टंकी से गिरे जर्जर हिस्से से कई लोग चोटिल भी हो चुके है। वहीं जर्जर टंकी को गिराकर नयी बनाने की मांग को लेकर सोमवार को वार्ड 49 पार्श्व प्रतिनिधि कमल दाधीच, पार्श्व दीनदयाल पारीक सहित कई लोगों ने एडीएम भागीरथ साख को ज्ञापन दिया। एडीएम को सौंपे गये ज्ञापन में जर्जर टंकी के नई नहीं बनने तक वहां सावधानी के लिए नये टंकाने व पुरानी टंकी को गिराकर नयी टंकी बनाने की मांग की गयी है।



सुजानगढ़ के वार्ड 49 में जलदाय विभाग की जर्जर टंकी।

राज्यपाल मिश्र ने गोविंद गुरु पुस्तकालय का लोकार्पण किया



माउंट आबू में गोविंद गुरु पुस्तकालय का लोकार्पण राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया।

जालोर/माउंट आबू, (कासं)। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सोमवार को आबूरोड में नगर सुधार न्यास आबू द्वारा विकसित गोविंद गुरु पुस्तकालय का लोकार्पण किया।

उन्होंने इस अवसर पर पुस्तक संस्कृति के विकास के लिए सभी की ओर से मिलकर प्रयास किए जाने का

आह्वान किया।

इस अवसर पर सांसद देवजी भाई पटेल, नीरज डांगी और विधायक आबू पिंडवाडा समाराम गोरसिया की भी विशेष उपस्थिति रही। राज्यपाल सोमवार प्रातः माउंट आबू से सड़क मार्ग द्वारा आबू रोड पहुंचे। वहां पहुंचने पर जन प्रतिनिधियों एवं जिला

प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका अभिवादन किया। राज्यपाल ने पुस्तकालय भवन के लोकार्पण के बाद वहां विकसित पुस्तकालय सुविधाओं, वाचनालय आदि का अवलोकन कर पुस्तक संस्कृति के लिए इन्हें महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने वहां उपस्थित बच्चों से संवाद भी किया।

करौली में यातायात व्यवस्था बद्दहाल, आमजन को परेशानी हो रही है

करौली, (निसं)। करौली शहर में यातायात पुलिस की ढिलाई के कारण व्यवस्था कमजोर होती दिखाई दे रही है जिससे दिनभर लोगों को जाम जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

करौली जिला मुख्यालय पर जिला पुलिस अधीक्षक के अलावा पुलिस के अन्य अधिकारी बैठते हो जिन्होंने शहर कि व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए यातायात शाखा को विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश देकर शहर के कई इलाकों को नो एंट्री जोन घोषित किया हुआ है जिसके तहत शहर के वजीरपुर गेट, हिण्डीन गेट, गणेश गेट से होकर प्रातः 8 बजे से शाम 7 बजे तक मालवाहक वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है इसके अलावा शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक शहर के सभी गेटों पर नो एंट्री जोन घोषित करते हुए ऑटो टैपों एवं चौपटिया वाहनों पर शहर में अंदर प्रवेश पर रोक लगा रखी है इसके बावजूद कोई पानना नहीं हो रही है। इससे ऐसा लगता है कि पुलिस अधीक्षक के आदेश बेअसर साबित हो रहे है। शहर के हिण्डीन गेट से गुलाब

■ शहर के कई इलाकों को नो एंट्री जोन घोषित किया हुआ है जिसके तहत शहर के वजीरपुर गेट, हिण्डीन गेट, गणेश गेट से होकर प्रातः 8 बजे से शाम 7 बजे तक मालवाहक वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है

बाग का मार्ग जिस समय गौरव पथ के रूप में विकसित किया गया था उस दौरान नगर परिषद की ओर से मार्ग को पूरी तरह नोन वैंडिंग जोन घोषित कर दिया इसके बावजूद इस मार्ग पर फल, सब्जियों के ठेले वालों ने कब्जा जमा रखा है और प्रभावशाली लोग अपनी दुकान और घरों के आगे सब्जियों के ठेले लगाने की एवज में उनसे मासिक रूप से भी वसूल करते हैं। यह मामला नगर परिषद के नगर



करौली में कोतवाली थाने के बाहर बिगड़ी यातायात व्यवस्था के चलते सड़क पर लगा वाहनों का जाम।

नियोजक के सामने भी आ चुका है मगर नगर परिषद प्रशासन की मिलीभगत के चलते ऐसे लोगों पर कार्यवाही नहीं हो रही है जिसके कारण सड़क पर लगने वाले धड़ी, ठेले शहर की यातायात व्यवस्था में अवरोधक बनकर आमजन की राह में रोड़ा बने हुए है।

यही नहीं करौली शहर के बड़ा बाजार, पुरानी सब्जी मंडी, भूधरा बाजार, फूटकोट चौराहा, जिला न्यायालय के मुख्य द्वार, कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार, टुक यूनिवर्सिटी पर अव्यवस्थित रूप से ऑटो, टैपों खड़े

रहने के कारण बार-बार जाम जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है वहीं गुलाब बाग चौराहे से रोडवेज बस स्टैंड मार्ग पर दुकानों के आगे चौपटिया वाहनों के खड़े रहने से पैदल राहगीरों को हाईवे की सड़क पर से होकर गुजरना पड़ता है।

राशिफल मंगलवार 13 जून, 2023



पंडित अनिल शर्मा

आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत् 2080, रेवती नक्षत्र दिन 1:32 तक, सौभाग्य योग प्रातः 5:55 तक, विधि करण प्रातः 9:29 तक, चन्द्रमा दिन 1:32 से मेष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-वृष, चन्द्रमा-मीन, मंगल-कर्क, बुध-वृष, गुरु-मेष, शुक्र-कर्क, शनि-कुम्भ, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग दिन 1:32 से सूर्योदय तक है। कुमार योग दिन 1:32 से आरम्भ होगा। भूद्रा प्रातः 9:29 तक है। पंचमि दिन 1:32 पर समाप्त होगा। आज मिन नमीनाथ जन्मति है।

सर्वश्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:02 से 10:44 तक, लाभ-अमृत 10:44 से 7:09 तक, शुभ 3:52 से 5:34 तक। राहुकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 5:37, सूर्यास्त 7:17

मेष
घर-परिवार के कार्यों के कारण भागदौड़ बनी रहेगी। घर-गृहस्थी के खर्चों में आनवश्यक वृद्धि हो सकती है। दिन के मध्यान्ध पश्चात व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। संभावित खोस से धन प्राप्त होगा।

वृष
अपने आर्थिक/वित्तीय मामलों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बने लगे। दिन के मध्यान्ध पश्चात मित्र-रिश्तेदारों के कारण समय खराब हो सकता है।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। दिन के मध्यान्ध पश्चात अटका हुआ धन प्राप्त होगा। परिवार में उन्स-सुविधाएं बढ़ेंगी।

कर्क
धार्मिक-मांगलिक कार्यों में भाग लेना का अवसर मिलेगा। धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

सिंह
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। स्वास्थ्य संबंधित मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। दिन के मध्यान्ध पश्चात अटके हुए कार्य बने लगे। व्यावसायिक सफलता से मनोबल बढ़ेगा।

कन्या
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। दिन के मध्यान्ध पश्चात अष्टम चन्द्र शुभ नहीं है।

तुला
व्यावसायिक विवादों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक अड़चनों दूर होने लगेगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। दिन के मध्यान्ध पश्चात परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे।

धनु
घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में दिवचर्य अस्त-व्यस्त हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधित मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।

मकर
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिवारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

कुंभ
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बने लगे। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। नवीन कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेगी। दिन के मध्यान्ध पश्चात महत्वपूर्ण मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।

मीन
अपनी कार्ययोजना को सीमित रखें। आवश्यक कार्यों में विन्य हो सकता है। शुभ कार्यों में व्ययधान सामने आ सकते हैं। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। यात्रा में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।